



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2019/आश्विन 2, 1941
No. 299]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2019/ASVINA 2, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2019

प्रकरण सं. 18/2019

विषय : बेलारूस, यूक्रेन, यूरोपीय संघ और पेरु के मूल के अथवा से निर्यातित 'एक्रिलिक फाइबर' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/25/2019 —डीजीटीआर.—यतः, मै. इंडियन एक्रिलिक्स लि., मै. वर्धमान एक्रिलिक लि. और मै. पशुपति एक्रिलोन लि. (जिन्हें आगे 'आवेदक' भी कहा गया है) ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष संयुक्त रूप से एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें बेलारूस, यूक्रेन, यूरोपीय संघ और पेरु (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा से निर्यातित 'एक्रिलिक फाइबर' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

- वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार का एक्रिलिक फाइबर है (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है)। एक्रिलिक फाइबर सिंथेटिक पालिमेर की एक लंबी श्रृंखला होती है जिसमें एक्रिलोनाइट्राइल इकाइयों (उत्पादन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री) के भार के अनुसार कम से कम 90 प्रतिशत होता है। एक्रिलिक फाइबर शब्दों में एक्रिलिक

स्टेपल, एक्रिलिक टो और एक्रिलिक टाप शामिल हैं। दूसरे शब्दों में एक्रिलिक स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक टो और एक्रिलिक टाप को वाणिज्यिक शब्दावली में एक्रिलिक फाइबर के रूप में जाना जाता है।

3. संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 55 के अधीन उपशीर्ष 5501.5503 और चार-अंकीय स्तर पर 5506 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। यह उत्पाद एचएस कोड 550130, 550330 और 550630 के अधीन शामिल है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

4. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

5. यह आवेदन संयुक्त रूप से मै. इंडियन एक्रिलिक्स लि., मै. वर्धमान एक्रिलिक्स लि. और मै. पशुपति एक्रिलोन लि. द्वारा दायर किया गया है। एक आवेदक कंपनी अर्थात् मै. वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड से संबंधित है इससे संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की थोड़ी मात्रा का आयात किया है। वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड द्वारा आयात की न्यून मात्रा को ध्यान में रखते हुए, वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड को नियम 2 (बी) के अर्थ के अंतर्गत भी पात्र घरेलू उद्योग माना गया है। अतः आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और पात्र घरेलू उद्योग हैं।

घ. संबद्ध देश

6. वर्तमान जाँच में शामिल देश बेलारूस, यूक्रेन, यूरोपीय संघ और पेरू हैं।

ड. सामान्य मूल्य

7. सभी संबद्ध देशों के मामले में सामान्य मूल्य को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों तथा तर्कसंगत लाभ को विधिवत रूप से समायोजित और जोड़ने के बाद उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित किया गया है।

च. निर्यात कीमत

8. आवेदक ने डीजीसीआईएंडएस के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमत को समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़े, कमीशन, और बैंक प्रभारों के लिए आवश्यक समायोजनों के पश्चात निर्धारित किया गया है।

छ. पाटन मार्जिन

9. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से अधिक है जिससे पता चलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन के निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है।

ज. जांच अवधि (पीओआई)

10. जाँच अवधि अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक की है क्षति जाँच अवधि में 2015-2016, 2016-17 और 2017-18 तथा जांच की अवधि की अवधियां शामिल होगी।

झ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

11. आवेदक ने दावा किया है कि उन्हें वास्तविक क्षति हुई है जैसा कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों द्वारा साक्ष्यांकित है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना से पता चलता है कि देश में क्षमता की उपलब्धता के बावजूद जाँच अवधि के दौरान पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। आयातों में वृद्धि, समग्र रूप से और उत्पादन और खपत की दृष्टि से हुई है। सकारात्मक कीमत कटौती, कम उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, लाभ, निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह में गिरावट से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।

ञ. जांच की शुरुआत

12. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं। अतः प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में ज्ञात आयातकों व को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें:

निर्दिष्ट प्राधिकारी**व्यापार उपचार महानिदेशालय****वाणिज्य विभाग,****वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,****चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,****5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

ड. समय-सीमा

15. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) जांच की शुरुआत की सूचना संबंधी प्राधिकारी के पत्र जारी होने की तारीख के चालीस (40) दिनों के भीतर प्रश्नावली के उत्तर और पाटनरोधी उपाय लागू करने अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यदि किसी हितबद्ध पक्ष से निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना

अधूरी होती है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार, रिकॉर्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

ढ. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

16. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।
17. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
18. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।
19. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/ रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
20. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
21. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

22. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

त. असहयोग

23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th September, 2019

[Case No: 18/2019]

Subject: Anti-Dumping investigation concerning imports of "Acrylic Fibre" originating in or exported from Belarus, Ukraine, European Union and Peru.

F. No. No. 6/25/2019-DGTR.— Whereas, M/s Indian Acrylics Limited, M/s Vardhman Acrylics Limited and M/s Pasupati Acrylon Ltd (hereinafter referred to as the applicants) jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the Rules) as amended from time to time, for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of "Acrylic Fibre" originating in or exported from Belarus, Ukraine, European Union and Peru (also referred to as the Subject Countries).

A. Product under consideration

2. The product under consideration is Acrylic Fibre of all types (hereinafter referred as subject goods). Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile units (major raw material for production). The terms acrylic fibre includes acrylic staple, acrylic tow and acrylic top. In other words, acrylic staple fibre, acrylic tow and acrylic top are known as acrylic fibre in the commercial parlance.
3. Subject goods are classified under chapter 55 of Customs Tariff Act, 1975 under the sub-heading 5501,5503 and 5506 at 4-digit level. The product is covered under HS code 550130, 550330 and 550630. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

B. Like Article

4. The applicants have claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The applicants have further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the domestic industry in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

C. Domestic industry & Standing

5. The application has been jointly filed by M/s Indian Acrylics Limited, M/s Vardhman Acrylics Limited and M/s Pasupati Acrylon Ltd. One of the applicant company, M/s Vardhman Acrylics Limited is related to Vardhman textiles Limited which has imported small quantity of the subject goods from amongst subject countries. Considering the small volume of imports by Vardhman textiles Limited, Vardhman Acrylics Limited has also been considered as eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b). The applicants therefore satisfy the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules and constitute an eligible domestic industry.

D. Subject Countries

6. The countries involved in the present investigation are Belarus, Ukraine, European Union and Peru.

E. Normal value

7. Normal value for all the subject countries has been constructed on the basis of cost of production, duly adjusted, and after additions for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

F. Export price

8. The Applicants have determined export prices on the basis of DGCIS transaction wise import data. The net ex-factory export prices have been determined after due adjustments towards ocean freight, marine insurance, port expenses, inland freight, commission and bank charges.

G. Dumping margin

9. The normal value has been compared with export price at ex-factory level. There is prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is higher than the ex-factory export price, showing that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters of the subject countries. The dumping margin is estimated to be above de minimis.

H. Period of Investigation (POI)

10. The period of investigation is April 2018- March 2019. The injury investigation period shall cover the periods 2015-16, 2016-17 and 2017-18 and the period of investigation.

I. Evidence of Injury and Causal Link

11. The applicants have claimed that they have suffered material injury as evidenced by volume and price impact of the dumped imports from the subject countries. Information provided by the applicants shows that imports of the product have increased despite availability of sufficient capacity in the country. The imports are undercutting the domestic prices and the same has led to price suppression. Increase in imports in absolute terms, and in relation to production & consumption, positive price undercutting, leading to decline in production, sales, market share, profits, return on investment and cash profit prima facie shows that injury to the domestic industry is due to dumped imports.

J. Initiation of the Investigations

12. And whereas, the Authority prima facie finds that evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; and injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exists to justify initiation of an anti-dumping investigation. The Authority accordingly initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

K. Submission of information

13. Known exporters in the subject countries, Government of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5 Parliament Street, New Delhi – 110001

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

L. Time limit

15. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to impose or otherwise of the anti-dumping measures within 40 days from the date of issue of letter by the authority intimating initiation of the investigation. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

M. Submission of Information on Non-Confidential basis

16. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set

marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either “confidential” or “non-confidential” at the top of each page

17. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non- confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (2) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties
18. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible
19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non- confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

22. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non- confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

O. Non-cooperation

23. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority